किसानों को नई ताकत : शिवराज

43 नई वैरायटीज होंगी शामिल

17 टेक्नोलॉजी और 14 प्रकाशन होंगे

विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का संकल्प

नई दिल्ली, 16 जुलाई. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 98वां स्थापना दिवस आज नई दिल्ली के भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लेक्स में मनाया गया.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का रोडमैप सामने रखा. उन्होंने एक तरफ 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को पहली बार नियमित नियुक्ति देकर खुशी साझा की, तो दूसरी तरफ 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, हर संस्थान से परिवर्तनकारी इनोवेशन, 10 करोड़ किसानों तक आईसीएआर टेक्नोलॉजी पहुँचाने, नकली बीजङ्कीटनाशक पर सख्त कानून और डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म जैसे ठोस लक्ष्य और संकल्प रखे. अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, उन पीढ़ियों को प्रणाम करने का दिन है जिनकी तपस्या ने अभाव को आत्मनिर्भरता में और संघर्ष को समाधान में बदला.

> 70 से अधिक एमओयू और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग समझौतों के ज़रिए इन तकनीकों को निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के सहयोग से तेज़ी से किसानों तक पहुँचाने की दिशा तय की गई ।शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर वैज्ञानिक की नौकरी केवल रोज़गार नहीं, बल्कि देश और दुनिया बदलने का मिशन है. उन्होंने श्रीकृष्ण के संदर्भ से बताया कि आदर्श कार्यकर्ता उत्साह से भरा, अहंकारङ्करहित, धैर्यवान और समन्वयकारी होता है और वैज्ञानिकों को भी इसी भाव से काम करना चाहिए. उन्होंने अपील की कि हर वैज्ञानिक किसानों के सपनों को अपना मिशन बनाए और अपनी पूरी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें.

एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ के रिलीज पर लगाई रोक

भुवनेश्वर. उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एली एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड की एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ के रिलीज करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने व्यवस्था दी है कि जारी रथ यात्रा उत्सव के दौरान इसे रिलीज करने से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम.एस. रमन की खंडपीठ ने एक आदेश में निर्देश दिया है कि अदालत की अनुमति के बिना या सुनवाई की अगली तारीख तक, जो भी पहले हो, फिल्म को 17 जुलाई या उसके बाद रिलीज नहीं किया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को तय की गयी है. यह अंतरिम आदेश महेश कुमार साहू और अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया है.

9वीं में तीसरी भाषा न लाएं, छात्रों पर बढ़ता है दबाव : सुप्रीम कोर्ट

- **जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सुनाया फैसला**
- **तमिलनाडु के नवोदय विद्यालय का मामला**

नई दिल्ली, 16 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाए जाने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करना उचित नहीं है,

इसी समय से छात्रों पर पढ़ाई और परीक्षाओं का दबाव बढ़ने लगता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि तीसरी भाषा की पढ़ाई 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू की जानी चाहिए और 9वीं कक्षा तक इसे पूरा कर लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा के बाद से विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है और ऐसे समय में नई भाषा जोड़ना छात्रों के लिए अतिरिक्त चुनौती बन सकता है. यह टिप्पणी उस समय आई जब तमिलनाडु सरकार की ओर से मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था.

> जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार नवोदय विद्यालयों का पूरा खर्च वहन करती है और राज्यों को केवल भूमि उपलब्ध करानी होती है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में नवोदय विद्यालय संचालित हैं, इसलिए तमिलनाडु में भी इन्हें स्थापित करने में बाधा नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि नीति में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा नहीं बताया गया है। अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों को राज्य की भाषा और अंग्रेजी के साथ किसी भी तीसरी भाषा का विकल्प दिया जा सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने उदाहरण देते हुए कहा कि तीसरी भाषा संस्कृत भी हो सकती है और यह आवश्यक नहीं कि वह हिंदी ही हो.

धारवाड़ में डॉक्टर की हत्या के बाद आठ साल के बेटे पर भी हमला

- **पत्नी के बदलते बयानों की जांच में जुटी पुलिस**

धारवाड़, 16 जुलाई. कर्नाटक के धारवाड़ में 45 वर्षीय एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. किरण होन्नावर की उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई, जबकि उनके 8 वर्षीय बेटे पर भी चाकू से हमला किया गया. घायल बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी डॉ. प्रियंका से पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अभी हत्या के समय तथा कारण को लेकर स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है. पुलिस के अनुसार, मामले का खुलासा तब हुआ जब डॉ. किरण के परिजन पूरे दिन उनसे संपर्क करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी. पत्नी ने परिजनों को अलग-अलग जानकारी दी.

बारां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी

बारां, 16 जुलाई. राजस्थान में बारां में गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों के दल मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट भवन को तत्काल खाली कराया गया और परिसर में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया.

2 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा

13 आरोपी गिरफ्तार करोड़ों की ठगी का मामला उजागर

कानपुर में पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार

कानपुर, 16 जुलाई. कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सचेंडी थाना क्षेत्र से 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

यह संगठित गिरोह खुद को पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी तथा अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को कथित अश्लील वीडियो मामलों में फंसाने, मुकदमा दर्ज कराने और जेल भेजने की धमकी देकर धन उगाही करता था. इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने सचेंडी क्षेत्र के गज्जापुरवा, नयापुरवा तथा आसपास के गांवों में एक साथ छापेमारी की. जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य खेतों और बागों में बनी झोपड़ियों में अलग-अलग समूहों में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए साइबर ठगी का संचालन कर रहे थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 29 मोबाइल फोन, तीन कारें तथा अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन और उपकरणों की जांच में 48 आईएमईआई नंबर और 68 मोबाइल नंबर सक्रिय मिले. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सत्यापन के दौरान इनसे जुड़ी 189 साइबर शिकायतें सामने आईं. 60 शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर इस गिरोह से संबंधित पाए गए. प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरोह ने दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के नागरिकों को निशाना बनाया.

सभी राज्य तीन महीने में बनाएं नीति : सुप्रीम कोर्ट

- **70 वर्ष से अधिक उम्र और बीमार कैदियों की करें रिहाई**

नई दिल्ली, 16 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र, लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी या शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की मानवीय आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में देशभर में ऐसे कैदियों की दयापूर्ण रिहाई के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि जेलों में बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई कैदी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.

सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे केजरीवाल

नई दिल्ली, 16 जुलाई. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल गुरुवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गई. इस दौरान सोनम वांगचुक का हेल्थ चेकअप किया गया तो उनका वजन लगभग नौ किलोग्राम कम रहा.

अनशन के दौरान उनके समर्थन में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज रहीं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिम्पल यादव के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर-मंतर पहुंचे और वांगचुक से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से वांगचुक की बात सुनने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार को संवाद करना चाहिए.

कीमती है वांगचुक की जिंदगी : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और कोर्ट को बताया कि इस मामले में मंगलवार को नोटिस जारी किया जा चुका है. कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएं क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि क्या सोनम वांगचुक की सेहत जांचने के लिए कोई तय व्यवस्था है.

ईग्नू में पंजीकरण की तिथि 31 तक

नई दिल्ली, 16 जुलाई. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में नए प्रवेश एवं पुन: पंजीकरण - की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है.

विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष अथवा अगले सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी 31 जुलाई तक ऑनलाइन पुन: पंजीकरण करने का अवसर प्रदान किया गया है. सभी प्रवेश एवं पुन: पंजीकरण की प्रक्रियाएं पूर्णत: ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जा रही हैं. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व एपीएआरआईडी, पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र तथा आरक्षण श्रेणी प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रतियां तैयार रखने की सलाह दी गई है. प्रवेश शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है.वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक एवं प्रमुख उमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इग्नू देश का अग्रणी केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो देश-विदेश के विद्यार्थियों के लिए 350 से अधिक स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालित कर रहा है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, लचीली, सुलभ एवं रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है.

साइबर खतरों-चुनौतियों के लिए रहें तैयार

डोभाल का बिम्सटेक देशों से आतंकवाद से निपटने का आह्वान

नई दिल्ली, 16 जुलाई. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्सटेक देशों से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आतंकवाद, साइबर खतरों, आर्थिक चुनौतियों और समुद्री सुरक्षा से निपटने के लिए आपसी सहयोग और ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि बिम्सटेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक भारत की मेजबानी में यहां हुई जिसमें सभी सदस्य देशों बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों से निपटने और आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध तथा साइबर खतरों से मिलकर लड़ने पर बल दिया।बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने, साइबर, समुद्री और ऊर्जा क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, कुशल आपदा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और नए तथा उभरते खतरों का सामना करने के लिए व्यावहारिक और परिणाम आधारित समाधानों पर चर्चा की.

> डोभाल ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के समुद्री पहलू के बारे में दिशानिर्देश अपनाए. ये दिशानिर्देश बिम्सटेक सदस्य देशों को क्षेत्र में तेज़ी से राहत कार्य करने में मदद करेंगे।उन्होंने समुद्र में संवाद के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कामकाज के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक सेट को भी मंजूरी दी.

टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा

कोलकाता, 16 जुलाई. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की राज्यसभा सांसद एवं अभिनेत्री कोयल मलिक (रूक्मिणी मलिक) ने गुरुवार को अपने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा.

उनके इस्तीफे के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर जारी राजनीतिक हलचल एक बार फिर चर्चा में आ गई है. सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कोयल मलिक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर भी पहुंचीं. इस मुलाकात के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर

इस्तीफे के बाद भूपेंद्र यादव से की मुलाकात

विभिन्न तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, उनकी ओर से किसी नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. कोयल मलिक को तृणमूल कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही राज्यसभा भेजा था. उनके इस्तीफे को पार्टी के लिए एक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है.

अगले सात दिन में होगी भारी बारिश

- **मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की जताई आशंका**

नई दिल्ली, 16 जुलाई. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण अगले सात दिनों के दौरान पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां काफी तेज होने वाली हैं.

मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि 19 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने जा रहा है। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों के कारण देश के कई राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज किए जाने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज 21 सेमी या उससे अधिक की अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। अत्यधिक बारिश के चलते ओडिशा के 23 जिलों और छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के निचले इलाकों में 17 जुलाई की सुबह तक अचानक बाढ़ आने की गंभीर चेतावनी जारी की है. इससे अधिकतम तापमान गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री के बीच आ जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. दूसरी तरफ, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में अगले दो दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहने के आसार हैं. मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में न जाने की सख्त सलाह दी है.

> इसके अलावा, उत्तराखंड में 18 से 21 जुलाई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 जुलाई के बीच मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में भारी जलभराव का खतरा बढ़ गया है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फिलहाल उमस भरी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि 17 जुलाई की शाम या रात से मौसम का मिजाज बदलेगा और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर शुरू होगा. इसके बाद 18 और 19 जुलाई को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहेंगे.

आज का इतिहास

1489- निजाम खान को सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया.

1712- इंग्लैंड-पुर्तगाल- फ्रांस ने युद्धविराम संधि पर हस्ताक्षर किए.

1850- हार्वर्ड वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया.

1893- इंग्लैंड के आर्थर श्रेत्सबरी टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने.

1919- यूरोपीय देश फिनलैंड में संविधान को स्वीकृति.

1929- सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त किए.

2035 तक जैव-अर्थव्यवस्था 691 अरब डॉलर का अनुमान

- **नीति आयोग ने भारत को अग्रणी जैव-अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाने की रूपरेखा जारी की**

नई दिल्ली, 16 जुलाई. नीति आयोग ने गुरुवार को 2035 तक भारत को अग्रणी जैव-अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाने की रूपरेखा जारी की.

इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 691 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जिससे 3 करोड़ से अधिक उच्च-कौशल वाले रोजगार सृजित होंगे और भारत दुनिया की शीर्ष तीन जैव-प्रौद्योगिकी शक्तियों में शामिल हो सकता है.

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस रूपरेखा का अनावरण करते हुए कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व जैव-प्रौद्योगिकी कर रही है. उन्होंने बताया कि वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान में 1.4 से 1.8 ट्रिलियन डॉलर के बीच है, जबकि भारत में 11,000 से अधिक जैव-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिन्होंने जैव-प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित नीति तैयार की है. उन्होंने कहा, अब भारत दूसरों के प्रयोगों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार है. 2047 तक 2.6 ट्रिलियन डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2047 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसकी हिस्सेदारी 8 से 10 प्रतिशत हो सकती है. इसके लिए जैव-विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जैव-प्रौद्योगिकी, नियामकीय सुधार और उद्योग की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की गई है.

छह राष्ट्रीय जैव मिशनों का प्रस्ताव- रूपरेखा में देश की जैव-प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत करने के लिए छह राष्ट्रीय जैव मिशनों का प्रस्ताव रखा गया है.

इंजीनियरिंग बायोलॉजी का नया पाठ्यक्रम शुरू होगा

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर जैव-प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार इंजीनियरिंग बायोलॉजी का पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो भविष्य की जैव-अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. 2014 के मुकाबले 16 गुना बढ़ी जैव-अर्थव्यवस्था- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के 10 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में 195 .3 अरब डॉलर हो गई है. वर्तमान में इसका योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4 .8 प्रतिशत है. डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मजबूत जैव-अर्थव्यवस्था से देश को स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, लाखों उच्च-कौशल रोजगार और वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

हस्तियों के ट्वीट

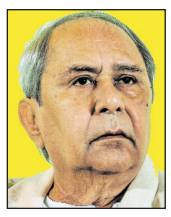

बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है कि रथयात्रा के दौरान भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान जाने की खबर से मैं अत्यंत दुखी हूं. मैं दिवंगत श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति और सौ से अधिक घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. इस दुख की घड़ी में, बीजू जनता दल के सभी कार्यकर्ता सभी की सहायता के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे.

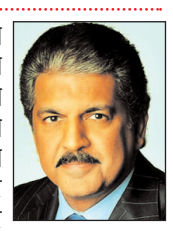

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है कि भारत की रक्षा क्षमता का भविष्य स्टार्टअप्स द्वारा आकार लेगा.इस स्टार्टअप ने अभी-अभी एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो शाहेद ड्रोन से भी बेहतर प्रदर्शन करता है. साधारण प्रयोगशाला या अव्यवस्थित परीक्षण क्षेत्र को देखकर भ्रमित न हों. ये टीमें बेहद उत्साही और कुशल हैं, और युद्धक्षेत्र में हर बदलाव के साथ अपने उत्पाद को नए सिरे से तैयार करती हैं.

सम्मेलन | गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक शस्त्रों के सम्मेलन में कहा

आगामी युद्धों में रणनीतिक भूमिका होगी निर्णायक

नई दिल्ली, 16 जुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों के बावजूद सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसे सामरिक अवसंरचना सैन्य अभियानों के लिए भविष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगी.

श्री सिंह ने गुरुवार को यहां सीमा सड़क संगठन रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाने वाली सड़क भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीमा पर तैनात सैनिक, इसलिए वसंरचना का निर्माण करने वाले भी राष्ट्रीय सुरक्षा के समान

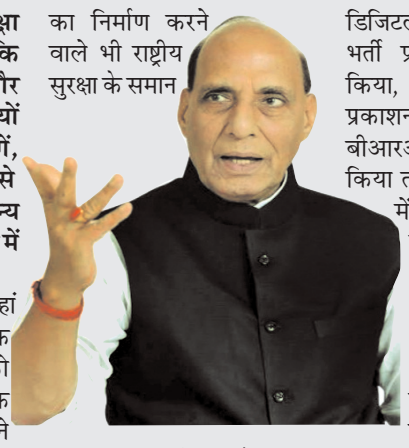

रूप से महत्वपूर्ण प्रहरी हैं.

श्री सिंह ने इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन की नई डिजिटल परियोजना प्रबंधन और भर्ती प्रणालियों का शुभारंभ किया, संगठन के तीन प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन किया, बीआरओ गान का अनावरण किया तथा अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को सम्मानित किया. दो दिवसीय सम्मेलन में सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक अवसंरचना विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और सतत निर्माण पद्धतियों पर विचार-विमर्श किया गया.

> रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की सराहना करते हुए कहा कि उसने एक साधारण सड़क निर्माण एजेंसी से विश्व के प्रतिष्ठित सामरिक संगठनों में स्थान बनाया है. उन्होंने अटल सुरंग, सेला सुरंग और उमलिंग ला दर्रा जैसी परियोजनाओं को संगठन की इंजीनियरिंग क्षमता और उत्कृष्ट कार्य का प्रतीक बताया. सरकार आधुनिक अवसंरचना और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है.